



विचार-मंथन

# रेपोरेट में कटौती से बढ़ेगी रप्तार या बनी रहेगी सुस्ती?

कर्ज सम्भालने का हिसाब इसी पर टिका होता है और इसका सीधा और पहला असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जिन्होंने घर, वाहन, अन्य सामान या फिर शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए बैंकों से ऋण लिया होता है। पहले दिनों अर्थव्यवस्था के लिहाज से स्वकारात्मक खुबरों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ की ओर से नीतिगत दरों में कमी से यही संकेत उभरता है कि महागाई अब नियन्यत्रण में है और आर्थिक मोर्चे पर खड़ी चुनौतियों से पार पाने में देश आगे की राह पर है। आरबीआइ ने शुक्रवार को प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो दर में 0.5 फीसद की कमी करके उसे 5.5 फीसद कर दिया। इसे उम्मीद से ज्यादा की कमी माना जा रहा है। इसके अलावा, एक चौंकाने वाले फैसले के तहत आरबीआइ ने बैंकों के लिए भी नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में भी एक फीसद की कटौती की घोषणा की। यह लगातार तीसरी बार है, जब

केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले आरबीआइ ने इसी वर्ष फरवरी और अप्रैल में पचास आधार अंकों की कटौती की थी। जाहिर है, यह न केवल देश के भीतर आर्थिक उत्तार-चाव से निपटने की कोशिश है, बल्कि फिलहाल दुनिया भर में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसमें इन उपायों से अर्थव्यवस्था को सभालने में भी मदद मिलेगी। रेपो दरों में कमी को मुख्य रूप से ऋण के लिहाज से सुविधाजनक माना जाता रहा है दरअसल, रेपो दरों में कमी को मुख्य रूप से ऋण के लिहाज से सुविधाजनक माना जाता रहा है। कर्ज सम्भालना या महागा होने का हिसाब इसी पर टिका होता है और इसका सीधा और पहला असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जिन्होंने घर, वाहन, अन्य सामान या फिर शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए बैंकों से ऋण लिया होता है या फिर वे लोग, जो इस बात का इंतजार करते हैं कि रिजर्व बैंक की ओर से कब नीतिगत दरों में



कमी की जाए और कर्ज समस्त होने के बाद वे कुछ खरीदने या निवेश करने की योजना बनाएँ। गौरताल है कि रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों के अनुरूप ही व्यावसायिक बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले प्रश्न और अन्य सावधि जमा के मद में व्याज की दरों निर्धारित करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि रेपो दरों में कमी के बाद व्यावसायिक बैंक भी कर्ज की दरें घटाएंगी। इसके बाद स्वाभाविक रूप से कर्ज समस्त होगा और मासिक किस्तों में कमी की बजह से बैंकों से प्रश्न लेने वाले उपभोक्ताओं की मांग बहु सकती है। साथ ही, पिछले कुछ समय में वाहन बाजार और खासतार पर जारी-जायदाद के कारोबार में जिस तरह की मंदी की आशंका जताई जा रही थी, नीतिगत दरों में कटौती के बाद उसमें सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। इस लिहाज से देखें तो रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बड़ी कमी की जो घोषणा की है, वह एक तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में एक अहम कदम है। मगर जरूरत इस बात की है कि इस तरह के फैसले सिफर घोषणाओं और अर्थव्यवस्था के जटिल गणित तक ही न सिमटे रहें। इसका असर जब तक जमीन पर नहीं दिखेगा, आम लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा, वे अपनी जरूरत के लिए घर या कोई अन्य चीज की खरीदारी करेंगे और सहज और निर्दृढ़ नहीं होंगे, तब तक इस तरह के फैसले अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को दूर करने में सहायक साक्षित नहीं हो सकते। महाराहा से गहर और क्रय शक्ति की सीमा में खरीदारी में सहजता से यह तथ लोगा कि रेपो दरों में कमी का साध आम लोगों तक कितना पहुंच पाता है। प्रश्न लेने का उत्साह उसे चुकाने की स्थितियों पर टिका रह सकता है। इसलिए रोजगार और आय के अन्य माध्यमों की बुनियाद मजबूत करने की स्थिति पैदा करनी होगी, ताकि लोग अपने निवेश और अन्य अर्थिक फैसलों को लेकर सुरक्षित महसूस करें।

अपने कार्यक्रमों में विभिन्न विचारों के महानुभावों को आमंत्रित करने की है संघ की परंपरा

लोकेन्द्र सिंह राजपूत

जो संघ को समझत है, उन्हें यह सब सहज हो नगता है। इसलिए नागपुर में आयोजित संघ लक्ष्यावर्ग 'कार्यकर्ता विकास वर्ग-2' के समापन मराठों में जब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के जनजाति वर्ग के कदाचित नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया गया, तब संघ को जाननेवालों को यह सहज हो लगा लेकिन संघ के प्रति संकीर्ण सोच खेनेवाले इस पर न केवल हैरानी बढ़ा कर रहे हैं वर्षपितृ वितंडावाद भी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, उनके वितंडावाद की हवा स्वयं जनजातीय नेता अरविंद नेताम ने यह कहकर नकाल दी कि जनवासी समाज की समस्याओं और चुनौतियों को संघ कार्यक्रम के माध्यम से खेने का सुअवसर मुझे मिला है। उन्होंने संघ के कार्यध में एक महात्वपूर्ण इटिप्पणी यह भी की है कि संघठन में चितन-मध्यन की गहरी परंपरा है। विविध में जनजातीय समाज के सामने जो चुनौतियां आनेवाली हैं, उसमें आदिवासी समाज को जो संभालनेवाले और मदद करनेवाले लोग/संगठन हैं, उनमें हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मानते हैं। सुप्रसिद्ध जनजातीय नेता अरविंद नेताम श्रीमती झूँदिरा गांधी और पीछी नरसिंह गवर्नरकार में मंत्री रहे हैं। उक्तेखनीय है कि संघ के कार्यक्रमों में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और जय प्रकाश नारायण से लेकर श्रीमती झूँदिरा गांधी एवं प्रणब मुख्यमंत्री तक शामिल हो चुके हैं। संघ ने कभी किसी से परहेज नहीं किया। संघ अपनी स्थापना के समय से ही सभी प्रकार के मत खेनेवाले विद्वानों से मिलता रहा है और उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघावाद में गहरा विश्वास है। वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भासवत कहते हैं कि अगर हम विचारों को एक किला बनाकर उसके पंड्य अपने आपको बढ़ा कर लेंगे तो यह



ज्यावाहारिक नहीं होगा। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवर प्रतिष्ठित राजनेता थे। कांग्रेस, समाजवादी एवं कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका गहरा परिचय था। संघ का दर्शन कराने के लिए डॉक्टर साहब लगातार विभिन्न विचारों के विद्वान् व्यक्तियों एवं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उन्हें संघ में आमंत्रित करते थे। ये उस समय की चुनौतियों के संबंध में सलझाए विचार-विवरण करके समाधान के मार्ग तक पहुँचने का प्रयास करते थे। संघ के वर्तमान ओखल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आधिकर अपनी पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ = स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र' में लिखते हैं कि किसी विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं, किन्तु जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो अवश्य ही समाधान निकलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1930 के दशक से ही समाज जीवन में सक्रिय लोगों को अपने कार्यक्रमों में जुलाता रहा है दरअसल, एक और महत्वपूर्ण बात है यह कि संघ को विद्यास है कि जब तक कोई संघ से दूर है, तब तक ही वह संघ का विरोधी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह संघ के विकास आता है और संघ को

ने तो संघ को नया नाम ही दे दिया था। उन अनुसार- आरएसएस अर्थात् रेडी फॉर सेल्टलेस सर्विस। संघ के कार्यक्रम में जब भी कोई अधिकारी विचार का व्याप्ति आया है, तब संघ के कार्यकर्ता की ओर से कभी उनका विरोध नहीं हुआ। बल्कि स्वयं को अधिक प्रगतिशील प्रवं लोकतांत्रिक बतानेवाले लोगों ने ही आमंत्रित महानुभावों रोकने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जब उन सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तब ये लोग आमंत्रित महानुभावों की छवि पर हमला करने लगते हैं। इस 'छिपा हुआ मंचों' घोषित कर देते हैं। यदि हो, तो 2018 में नागपुर के रेशिमबाग में आयोजित संशिक्षा वर्ग-नृतीय वर्ष के समापन समारोह में जब पूर्व राष्ट्रीय प्रणव मुख्यमंत्री के शामिल होने समाचार सामने आया, तब कितना हो-हड्ड मच गया। प्रणव दा को रोकने के लिए पत्र लिखे रखा आज्ञान किए गए। आखिर में प्रणव दा समारोह पहुंचे और अपना ढोधोधन दिया। इस अवसर प्रणव दा न केवल आद्य सरसंघचालक हेडगेवर के घर (संग्रहालय) गए, बल्कि वह उन्होंने विजिटर बुक में लिखा- मैं आज भारत के महान सपूत डॉ. केंबी हेडगेवर के प्रति सम्मान और ब्रह्मांजलि अर्पित करने आया हूँ। रिपब्लिक पार्टी औफ इंडिया के नेता और दलित दादासाहेब रामकृष्ण सूर्योदाम गवई तथा कम्युनिटी विचारों वाले जस्टिस बीआर कृष्णा अख्यर भी संघ के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मोनाशीपुरम में वह हिंदूओं द्वारा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार विजान की घटना के बाद श्री गवई ने स्वयं संघ कार्यक्रम में आने की इच्छा व्यक्त की थी तो वह अपने विचार रखे थे। केरल की पहली कम्युनिटी सरकार में मंत्री रहे जस्टिस बीआर कृष्णा अख्यर स्थानीय विरोधों के बावजूद तत्काल सरसंघचालक से संपर्क किया और बाद में पत्रकों के सामने अपने विचार सखे थे।

**डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हैरान करने वाला- भारत को नए रास्ते पर जाना ही पड़ेगा!**

भारत की घेरेलू राजनीति में मध्य बवाल के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रॉप लगातार अपने दावों को दोहरा रहे हैं और इससे यह चात साफ होती जा रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की सामग्री का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव फिल्हाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत की बहादुरी सेना से युरी तरह से मात खाने के बाबजूद पाकिस्तान का बड़बोलापन जारी है। भारत जैसे ताकतवर देश के लिए पाकिस्तान कोई बड़ी चुनौती नहीं है लेकिन वह आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का अभिन्न अंग बना चुका है। ऐसे में सब कुछ जानने और समझने के बाबजूद दुनिया के कई देशों का विचित्र रखिया कापी हैरान करने वाला है। चीन के डर को तो समझा जा सकता है बर्योकि उसने

आजाद होने के बाद से ही भारत की सभी सरकारें ने बातचीत, संवाद और शांति की हमेशा व्यक्तिगत की। भारत के बिना आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मफलता मुनिष्ठित नहीं हो सकती लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों और फैसलों से भारत के लिए लगातार असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। चुनाव के बाल पर अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके हर बयान का असर भारत की घेरलू राजनीति पर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वह लगातार, दुनियाभर में घूम-घूम कर बह दाढ़ा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया था। भारत द्वारा इनकार करने के बावजूद ट्रंप चुप होने को तैयार नहीं है

मोदी और सत्तासङ्क मठवंधन के लिए असहा स्थिति पैदा करता हुआ नजर आता है। भारत में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दल गोनालड ट्रॉप के बवानों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर सरेंडर करने का आशेष लगा रहे हैं। देश के 16 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक गुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पक्ष लिखकर, इन तमाम ममलों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इससे यह बात साफ होती जा रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की साख का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करना चाहते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक मंत्री हावड लुटनिक ने तो खुलकर कहा दिया है कि भारत द्वारा रूस से सैन्य साजो-सामान खरीदने और ब्रिक्स समूह में शामिल होने के

**लू से 700 मौतें हो गई, राजनीतिक दलों ने उपर तक नहीं की**

योगेन्द्र योग

मुझा यदि बोट बैंक से जुड़ा हुआ हो, तर्हंग राजनीतिक दल कुछ गंभीरता व्येशक दिखाएं ले कि किन्तु लोगों के जीवन-मरण जैसे मुद्दे से लगता था ही है कि उनका कोई सरकारी नहीं रह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो अदालतों को मौसम की मार से होने वाली भौतिकों के लिए सरकारों को दिशानिर्देश नहीं देने पड़ते। आखर्य की बात यह है कि प्रतिकूल मौसम से आम लोगों के बचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के सरकारों की है, किन्तु यह काम भी अब अदालतों को करना पड़ रहा है। इससे सचाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारों की जरूरत कितनी सीमित रह गई है हीटिंग से 700 से ज्यादा भौतिकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि इनके बड़े मौसम संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमुद्दी ऑफिस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गृह भवित्व, परिवर्तन, चन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकरता विकास तोंगड़ ने दाखिल की उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि सरकारों को गर्भी की जैतावनी देने वाली प्रणाली हीटिंग की पहले से जानकारी देने की व्यवस्था, और 24 घण्टे काम करने वाले राहत हेल्पलाइन जैसी मुविधाएं लायू करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में यह भी जताया गया है कि 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीटिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए थे लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक उस पर काम ही नहीं किया याचिका में यह भी जित्र है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की आपदा से निपटने वे लिए पुछता इंतजाम करे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कह कर्तव्य कि पिछले साल दिए गए अदालत ने निर्देशों को ठंडे बस्ते में ढाल दिया गया कोर्ट ने कहा कि यह कानून के शासन पर सचाल उड़ाता है। अधिकारी स्वयं कंकानी से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कोई आखिर बंद करके नहीं बैठ सकता। इसाने से जानवरों जैसा जर्ताव नहीं हो सकता।



सचिव से अद्यालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्यपोजना बनाने का निर्देश दिया, जहाँ केन्द्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केन्द्र व राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में गर्मियों के दौरान पड़ने वाली लू के महेनजर 11 राज्यों से कहा है कि वे कमज़ोर लोगों, खासकर अधिक रूप से कमज़ोर गर्मी, बाहरी कामगारी, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू के कारण 3,798 लोगों की मौत के बारे में एनसीआरसी के अंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, कार्य घटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है। भारत में वर्ष 2001 से 2019 के बीच हीटवेट यानी लू से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि पुरुषों में लू से होने वाली मौतों की आशका ज्यादा पाई गई। एक और हालिया अध्ययन में यह बताया गया है कि हीटवेट से होने वाली मौतें जातीय आधार पर भी बटी हुई हैं। भारत में हाशिए पर भौजूद समुदायों से ताङ्कुक रखने वाले लोगों की मौत, अन्य समुदायों की तुलना में, लू से कहीं ज्यादा हुई। अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एक तरह की थर्मल



